S.No.	Name of State/Union Territories	Whether CAD Authorities	
		Constituted	Not Constituted
20.	Tamil Nadu	—	Not constituted #
21.	Tripura	—	Not constituted #
22.	Uttar Pradesh	Constituted	—
23.	West Bengal	Constituted	—
	UNION TERRITORIES		
1.	Dadra and Nagar Haveli	—	Not constituted* #
2.	Daman and Diu	—	Not constituted* #

* Work is being implemented by Gujarat Government under Damanganga Project.

CAD Authorities not constituted and the Programme is implemented by the concerned Departments of the

Project under National Water Management Programme in Orissa

2775. SHRI RAHASBIHARI BARIK: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether projects under the National Water Management Programme are under implementation in orissa;

(b) if so, the details thereof alongwith project cost;

(c) the acres of land likely to be irrigated thereafter; and

(d) the details of the objectives of the above programme?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WATER RESOURCES (SHRI SOMPAL): (a) to (d) No, Sir. The Would Bank assisted National Water Management Project (NWMP) has closed on March 31, 1995. The project objective was to increase agricultural productivity and farm incomes through the provision of more reliable, predictable and equitable service. Eight schemes of Orissa state covering a Culturable Command Area of 1.07 lakh hectares were taken up for implementation under NWMP at an estimated cost of Rs. 34.43 crore. However, none of the schemes could be completed during the project duration.

ए० आई० बी० पी के अंतर्गत उत्तर प्रदेश को ऋण

2776. **श्री मनोहर कान्त ध्यानी:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1998-99 में उत्तर प्रदेश सरकार ने ए० आई० बी० पी० योजना के अन्तर्गत दस परियोजनाओं हेतु 168 करोड़ रुपए का ऋण स्वीकृत करने का प्रस्ताव भेजा था;

(ख) क्या यह भी सच है कि अब तक 93 करोड़ रुपए के ऋण की स्वीकृति दी जा चुकी है और 46.58 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त हो गयी है;

(ग) शेष 75 करोड़ रुपए का ऋण स्वीकार न करने के क्या कारण है; और

(घ) क्या सरकार वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर इस योजना की स्वीकृत राशि को व्यपगत (लैप्स) होने से छूट प्रदान करेगी?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल): (क) से (घ) उत्तर प्रदेश सरकार के लिए वर्ष 1997-98 के दौरान 153.00 करोड़ रुपये की केन्द्रीय ऋण सहायता स्वीकृत की गई थी जिसमें से केवल 78.00 करोड़ रुपये जारी किए गए क्योंकि राज्य सरकार ने वर्ष 1997-98 के दौरान समय से उपयोग प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किया। राज्य ने वर्ष 1998-99 के दौरान अपनी 10 परियोजनाओं के लिए त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत 168.00 करोड़ रुपये की केन्द्रीय ऋण सहायता प्रदान करने का अनुरोध किया। इन परियोजनाओं में 5 नई परियोजनाएं थीं और वर्ष 1997-98 के दौरान केन्द्रीय ऋण सहायता प्राप्त कर चुकी लखवर व्यासी इसमें